

सम्पादकीय

संभव है दूसरी पीली क्रांति,
लेकिन जीएम सरसों को
लेकर कई चिंताओं का
समाधान करना जरूरी

जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल समिति यानी जीईएसी द्वारा जेनेटिकली मोडिफाइड (जीन संवर्धित-जीएम) सरसों की खेती को मंजूरी देने की सिफारिश करने के साथ ही इसका समर्थन और विरोध शुरू हो गया है। जहां समर्थक उत्पादन में बढ़ोतारी का दावा कर रहे हैं, वहां विरोधियों का तर्क है कि जीएम सरसों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को सार्वजनिक नहीं किया गया और इसके पैदावार संबंधी दावे संदिग्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मांग के अनुरूप घरेलू उत्पादन न होने से देश में खाद्य तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का 65 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पामोलीन और सूरजमुखी के तेल का होता है। खाद्य तेल महाराष्ट्र के दौर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जीईएसी ने देश में जीएम सरसों धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 (डीएमएच 11) की खेती को हरी झंडी दिखाई दी है। जीएम सरसों पहली खाद्य फसल है जिसकी ऐसी खेती की अनुमति मिली है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसका फील्ड ट्रायल होगा, फिर इसे व्यावसायिक रूप से जारी किया जाएगा। इसके पहले 2017 में भी जीएम सरसों के फील्ड ट्रायल को अनुमति दी गई थी, लेकिन किसान संगठनों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। कमोबेश यही हश्च बीटी बैंगन का भी हो चुका है। डीएमएच 11 सरसों को दिल्ली विवि में सेंटर फार जेनेटिक मैनिपुलेशन आफ क्राप लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि डीएमएच 11 सरसों की मौजूदा किस्मों के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक उत्पादक है। डीएमएच 11 में दो लहियन जीन होते हैं। इन्हें एक जीवाणु से अलग किया जाता है। यह ज्यादा उपज देने वाले सरसों के प्रजनन को सक्षम बनाता है। इन्हें विशेषताओं के चलते आस्ट्रेलिया ने भारतीय जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति दे दी है। सरसों की मौजूदा घरेलू किस्मों की औसत उत्पादकता 1.2 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत दो से 2.20 टन है। यह दावा किया जा रहा है कि जीएम सरसों की खेती से देश की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। देश में 65-70 लाख हेक्टेयर भूमि

कश्मीर में अभी बाकी है लड़ाई, अलगाववाद और 'काफिर-कुफ्र' वाले चिंतन के विरुद्ध यद्दृ अब भी जारी

हाल में जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। ऐसे ही एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण सेदेश में कहा, 'अपने बाकी बचे हिस्से गिलगित और बालिटस्तान तक पहुंचे बिना जम्मू-कश्मीर अधिकार गुलाम कश्मीर न केवल भारत का भौगोलिक हिस्सा है, अपितु अनादिकाल से सांस्कृतिक भारत का भाग भी है। यहां हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋचाओं का जन्म हुआ था। सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने अपनी दिविजय यात्रा' का समापन प्राचीन कश्मीर में किया था। तब

A photograph showing a group of men in traditional Pashtun attire, including white turbans and shawls, standing in a dry, arid landscape. Some individuals are holding RPG launchers, suggesting they are members of the Taliban or similar extremist group.

है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया है। हमारी यात्रा तभी पूरी होगी, जब हम 22 फरवरी, 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके कर्त्ता को प्रणाम जरूर मिलेगा।' कश्मीर पर भारत सरकार का यह दृष्टिकोण विलंबपूर्ण ही सही, किंतु स्वागतयोग्य है। इसमें संदेह नहीं कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लेकर हमेशा छल-कपट का ही सहारा लिया है। यह पाकिस्तानी कुठिलता का ही प्रमाण है कि उसने गुलाम कश्मीर की पहचान बदलने के लिए उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है, जबकि उसकी 40 लाख की आवादी में 70 प्रतिशत लोग पौठोहारी भाषी हैं। पौठोहारी पंजाबी भाषा की ही एक उप-भाषा है। ऐसा ही विरोधाभास उसके 'कौमी-तराने' को लेकर भी है। पाकिस्तान की भाँति है। जिमनास्योगर भानु हारे राम

डिजिटल पर दिख रहा वर्दी का दम, ओटीटी पर कहानीकारों को मिला खुला मैदान

हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रेखा, प्रियंका चोपड़ा से लेकर रानी मुखर्जी तक कई कलाकारों ने फिल्मों में पुलिस अधिकारी के पात्रों को उसकी भाषा ऊपर से दबाव होता है। काम के अनुपालन के नियम हैं। अनदेखी और केंदी दोनों बेब सीरीज में पुलिस वाले हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनकी आसपास की जरूरतें क्या हैं, उसके मताबिक उनकी

आचार्य कहते हैं, 'आरण क थिलर जानर में है। फिर भी हमने उसे वास्तविक रखते हुए महिला पुलिसकर्मी की चुनौतियों और जीवन पर फोकस किया था। हम जानर के अनुरूप पात्र को लिखते हैं। अभी

का निजी जीवन भी होता है उसे आप कैसे दर्शाएंगे। उसका कोई अतीत हो सकता है। कोई दुविधा हो सकती है। यह सब कहानी के मताविक ही करना पड़ता है। जब मैंने अरण के लिखा था तो मेरे

अलग होगी। उसके प्रोफेशन का उसके जीवन पर क्या असर होगा। डेल्ही क्राइम में शेषाली शाह का किरदार देखें तो वह अलग लेवल की ही पुलिस अधिकारी है। विजिटरल लॉर्पार्म पर अधिकेविरों

मजा आया। हिंदी सिनेमा में फेफड़कार रोहित शेष्टी पुलिस की दुनिया रचने के लिए जाने जाते हैं। अब इस दुनिया को आगे बढ़ाते हुए वह डिजिटल प्लेटफार्म तक पहुंच गा दें। तब इंडियान परिस्थ



भूमिकाएं बनाई जाती हैं। महिला पुलिस अधिकारी के सामने भी नौकरी व परिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने चुनौतियां होती हैं। पाताल लोक का पुलिस गाठा सुपरहीरो नहीं है, अनदेखी का पुलिस गाला घोष सुपरहीरो नहीं है। अपराधियों के बीच उनकी जिंदगी निकल गई है, तो वे उन्हें अच्छे से जानते हैं, लैकिन उसे सही तरीका नहीं पता था या वह ८० तने महत्वाकांक्षी नहीं थ कि आगे नहीं बढ़ पाए। पुलिस तंत्र के आसपास बुने शो के लेखन को लेकर आरण् क बेब सीरीज के लेखक चारुदत्

मैंने एक शो लिखा है दुरंगा वो कोरियन शो का रीमेक है। वह बहुत ज़्यादा नाटकीय है। जब कहानी वास्तविक ना हो तो उसमें हम थोड़ी स्वतंत्रता लेते हैं। वास्तविक कहानियों में पुलिस का जो प्रोटोकाल होता है उसमें भी शहर और गांव का फर्क होता है। दर्शकों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि गार्क ऐसा होता है। हालीवुड फिल्म की तरह हम कापी नहीं कर सकते। अगर हम उनको कापी करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे यहां ऐसा कहां होता है। पुलिस से जुड़ी कहानियों में नायक

लिए उसमें थ्रिलर एंगल जरूरी था उतना ही कस्तुरी डोगरा का पात्र। उसके पति और बच्चों के साथ उसका रिश्ता उसका छेटे शहर से होना और बड़े शहर से आए अधिकारी साथ उसके मतभेद। उन दोनों पर भी उतना ही धूप दिया था जितना बाकी कहानी पर दिया था। शायद उस वजह से वह लोगों को पसंद आया। दिली या मुंबई की महिला अधिकारी आपको एक समान नहीं दिखेंगी। उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, परिवेश अलग होगा। अगर शादीशुदा है तो उसकी जिंदगी थोड़ी

को पुलिसकर्मी बनने का भी काफी मौका मिल रहा है। आरण्यक का दूसरा सीजन अगले साल लाने की तैयारी है। शो में पुलिस अफसर की भूमिका निभाने को लेकर रवीना का कहना है कि मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि मुझे पुलिस अफसर का रोल मिला। मैं वास्तव में पुलिस में आना चाहती थी। वो हमेशा से मेरा सीक्रेट ड्रीम था। मैं हमेशा बोलती थी कि किरण बेदी (पर्व पुलिस अधिकारी) मेरी आदर्श है। किसी फिल्म में मुझे ऐसा सशक्त पुलिस अधिकारी की भूमिका नहीं मिली। आरण्यक करने में बहुत

कहते हैं आरण के में मायावी शक्तियों को जोड़ा था। ओटोटी की सुंदरता यह है कि यह खुली किताब है। अगर आप एक दिलचस्प कहानी लेते हों और उसमें एक जानर फिक्करते हो तो लोग देखेंगे। इसमें रोमांटिक ड्रामा, पालिटिकल थ्रिलर, हारर, कामेडी, सब बना सकते हैं। हर जानर को शामिल करते हुए आप पुलिस ड्रामा को बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी जानर तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। पुलिस का किरदार समाज का अहम हिस्सा होता है।

योगी सरकार की नई औद्योगिक नीति 'सामूहिक प्रयास और सामृहिक विकास' का आधार बनेगी

नोएडा पहले उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखण्ड को औद्योगिक रफ्तार देने वें लिए अगर किसी मुख्यमंत्री का नाम आम आदमी के जैहन में आता है तो वह दिवंगत नारायण दत्त तिवारी हैं। नारायण दत्त तिवारी ने अपने छोटे-छोटे और असंतुलित कार्यकालों के दौरान नोएडा जैसे शानदार औद्योगिक शहर की नींव रखी। गाजियाबाद को औद्योगिक रफ्तार दी। गिरते कानपुर को संभाला था। लखनऊ, भदोही, बनारस और यूपी के कई दूसरे ज़िलों में औद्योगिक डिकॉडरां एक्सप्रेसरे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसरे योगी सरकार आने से पहले से चल रहे हैं। इनकी लम्बाई 492 किलोमीटर है। पिछले साढ़े पांच वर्षों में योगी अदित्यनाथ सरकार ने बुंदेलखण्ड एवं सप्रे सरो, दिल्ली-मेरठ एवं सप्रे सरो और पूर्णांचल एक्सप्रेसरे परे किए हैं। इन तीनों एक्सप्रेसरों की लम्बाई 706 किलोमीटर है। इस तरह उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1,225 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेसरे हैं। अब 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेसरे 91 किलोमीटर लम्बे तो भूखंड आवंटन भ्रष्टाचार का जरिया बन गया था। पिछली सरकारों के कार्यकाल में ऑटो रिक्शा वाला बता देता था कि किस श्रेणी की जमीन पर कितना पैसा अंडर टेबल जाएगा। वह यह भी कह देता था कि उसका एक रिस्तेदार जमीन दिलवा सकता है। इस स्थिति पर इस सरकार ने सफलतापूर्वक काबू पाया है। अब नई प्रस्तावित नीति में फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन की व्यवस्था की गई है। फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन कितना लाभकारी है, इसका एक उदाहरण समझिए।

आपूर्ति के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पेश की गई है। साथ ही जलपूर्ति, जल निकासी और लॉजिस्टिक्स के विस्तृत उपाय हैं। वित्तीय संसाधनों की सुलभता के लिए अवस्थापना विकास कोष बनेगा। सरकार स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से इक्विटी पंजी जुटाने में मदद देगी। इस पॉलिसी में आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन, अनुसंधान व विकास, नवाचार और बौद्धिक सम्पदा अधिकार को प्रोत्साहन, गुणवत्ता और डिजाइन को प्रोत्साहन, प्रमाणापर्वती और ओपीपी और

ही उच्च रोजगार सृजन क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे हथकरघा एवं वस्त्रोदयोग, एमएसएमई व स्टार्टअप्स पर केंद्रित है। राज्य का नीतिगत ढांचा, स्वरोजगार और आड़ीओपी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार सृजन होगा। यह नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने में सहायक हो सकती है। इस सबके लिए समांतर रूप से 'ब्रॉन्ड उत्तर प्रदेश' को विकसित करना होगा। यह इमेज हासिल करने के लिए चिठ्ठेश को पोत्यादिन और

हैं। अगर कम्पनी राज्य के बुन्देलखण्ड और पूर्वाचल में इकाई स्थापित करती है तो जमीन खरीद पर लगने वाला स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब, 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूरे मध्यांचल में यह छूट 75 प्रतिशत दी जाएगी। पश्चिमांचल में यह रियायत दो हिस्सों में बांट दी गई है। वेस्ट यूपी के गौतमबुद्ध नगर और गणियाबाद जनपदों को छोड़कर बाकी क्षेत्र में 75 प्रतिशत छूट स्टांप ड्यूटी में सरकार देगी। अगर खायेंग गौतमबुद्ध नगर और



ग्रेटर नोएडा में हीरानंदानी समूह ने इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर की शुरुआत योगी आदित्यनाथ से करवाई है। यह समूह इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 600 करोड़ रुपये लेकर उत्तर प्रदेश में आया था। आवेदन के बाद महज एक सप्ताह में भूमि आवंटन ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने कर दिया। एक महीने में निर्माण शुरू और एक साल में पूरा हो गया। 'फास्ट ट्रैक मॉड' का फायदा यह हुआ कि अब हीरानंदानी समूह पूरे उत्तर प्रदेश में 39,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। जिससे यूपी देश में सबसे बड़ा डाटा हब बन जाएगा। समूह के प्रवर्तक राज्य के औद्योगिक माहाल से गदगद हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों को अराजकता ने तबाह किया। उस कोढ़ में बिजली की किल्लत खाज बनी रही। प्रस्तावित नीति में उद्योगों को निर्बाध बिजली

अन्य स्थानीय उद्योगों की सहायता को समाहित किया है। मुख्यमंत्री और राज्य के तमाम लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में इसका पांचवा स्थान होगा। जाहिर सी बात हैं, इतना बड़ा राज्य अस्थिर अर्थव्यवस्था के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अगर करीब 25 करोड़ जनसंख्या का सदोपयोग नहीं कर सकते तो यह पूरे देश के लिए अभिशाप बन सकती है। यह इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का विजन पेश करती है। इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता दिखाती है। भारी भरकम जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर वृद्धि जरूरी है। नई नीति रोजगार के अवसर सजित करने के लिए बड़ी इंडस्ट्री को विशेष प्रोत्साहन तो देती है, साथ

समाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। राज्य में और राज्य के बाहर लम्बे असे से रोजगार की तलाश युवाओं के पलायन की वजह रही है। यह नीति परे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देगी। इस सरकारी नीति में उद्योगों से अछूते बन्देलखण्ड और पूर्वाचल को फोकस में रखा गया है। मसलन, बुदेलखण्ड में 20 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 30 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्क बनाने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश के बाकी किसी भी हिस्से में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकासित निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई उद्योग नीति में भौगोलिक आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान और स्टाम्प शुक्र जैसी छोट की व्यवस्था समरप्ता लाने के लिए

श्रेणी में रहेंगी। पॉलिसी में है कि 500 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 3,000 करोड़ रुपये से कम पूंजी निवेश को सुपर मेगा श्रेणी में माना जाएगा। 3,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर यह नीति बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेंगवल सरकार वालाने के लिए नहीं उत्तर प्रदेश को अपने पांचों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नि:संदेह यह पॉलिसी अगले साल फरवरी में होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रस्ताव ला सकती है। उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन इकोनॉमी' बनाने में मददगार होगी। 'ब्रांड उत्तर प्रदेश' को दर्शकों से ऐसी ही सोच की दरकार थी। सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ 'सामूहिक प्रयास' और 'सामूहिक विकास' पर जोर दे रहे हैं।

